सरकार रोजगार प्रधान विकास पर बल देगी-- श्रम पुरस्कार वितरण समारोह में प्रधानमंत्री जी का भाषण

अक्टूबर 4, 2004
नई दिल्ली

मुझे इस वर्ष के श्रम पुरस्कार समारोह के अवसर पर आज आपके बीच उपस्थित होकर खुशी हो रही है। मैं सबसे पहले पिछले दो वर्ष-2002 तथा 2003 के सभी विशिष्ट पुरस्कार विजेताओं का अभिनंदन करना चाहूँगा। आज इस अवसर पर हम राष्ट्र सेवा में आपकी प्रतिबद्धता, समर्पण की भावना और कर्मठता का सम्मान करते हैं। आपने असाधारण एवं उत्कृष्ट प्रयास किए हैं। और यह स्वीकार करते हुए देश वस्तुतः राष्ट्र निर्माण के कार्य में हमारे समूचे श्रमिकवर्ग के योगदान को स्वीकार करता है। मैं आपकी ठोस उपलब्धियों के लिए आपको बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि आप राष्ट्र निर्माण के कार्य में लंबे समय तक सार्थक योगदान देते रहें।

महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि, "देश करोड़पतियों के बिना और पूंजीपतियों के बिना काम चला सकता है लेकिन मजदूरों के बिना किसी भी देश का गुजारा नहीं है" आजादी के बाद भारत ने जो महत्वपूर्ण औद्योगिक उपलब्धियाँ हासिल की हैं वे हमारे कामगारों और किसानों की कड़ी मेहनत और कर्तव्य-निष्ठा के बल पर ही हासिल हुई हैं। निःसंदेह नई व बेहतर वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय तकनीकों के इस्तेमाल के साथ-साथ यह आपके ही प्रयासों का फल है कि हमारे लिए कई क्षेत्रों में आत्म-निर्भर बनना संभव हो पाया है। संगठित उद्योग और अनौपचारिक सेक्टर दोनों ही में आपके प्रयासों ने हमें आयात किए जा रहे उत्पादों के अनुकल्पों का उत्पादन करने और महत्वपूर्ण निर्यात क्षमताओं का निर्माण करने में मदद दी है और हमारे भीतर नवीनता और उत्कृष्टता हासिल करने की भावना बढ़ाई है जो अभाव और शोषण के भय से मुक्त एक नए भारत के निर्माण का ठोस आधार है।

हमें इन उपलब्धियों पर ही संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना चाहिए। अपनी अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने का काम, राष्ट्र-निर्माण का काम और ईमानदार तथा संपूर्ण समाज में प्रतिस्पर्धी आर्थिक माहौल बनाने का काम एक लंबा और कठिन कार्य है। आज की वैश्वीकृत दुनिया में, जहां विकसित और विकासशील सभी देशों की अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर एक दूसरे से जुड़ती जा रही है तथा एक दूसरे पर निर्भर होती जा रही है, ऐसे में आज हमारे सामने प्रतिस्पर्धा और बढ़ती असमानता की दोहरी चुनौतियाँ खड़ी हैं। असमानता देशों के बीच हो सकती है, देश के भीतर हो सकती है और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच हो सकती हैं। हमारी सरकार यह मानती है कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए समाज के सभी वर्गों और खासकर भारत के श्रमजीवीवर्ग को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।

इस संदर्भ में, मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारी सरकार रोजगार प्रधान विकास और खासकर हर नागरिक को काम का अवसर प्रदान करने पर विशेष बल देगी। पिछले कुछ वर्ष रोजगार रहित विकास के वर्ष रहे हैं। और हम इस प्रवृत्ति को बदलना चाहते हैं ताकि ज्यादा विकास श्रमिकवर्ग के लिए सार्थक परिणाम दे सके। इसलिए मैं सुझाव देता हूँ कि अब समय आ गया है कि हम **"गरीबी हटाओ"** के नारे के साथ-साथ आज के जमाने का एक नया नारा **'रोजगार बढ़ाओ'** भी लगाएं।

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारी सरकार ने कई रणनीतियाँ तैयार की हैं, इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

प्रथमतः हम देश के 150 पिछड़े जिलों में **"काम के बदले अनाज"** का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी की दिशा में पहला कदम होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी स्वस्थ ग्रामीण व्यक्तियों को साल में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना होगा। इस कार्यक्रम के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है और अनुमोदन प्रक्रिया पूरी हो जाने पर, जो कि मैं समझता हूँ, कुछ दिन में पूरी हो जाएगी, हम अगले कुछ सप्ताहों में इसे आरंभ करना चाहते हैं। अगले कुछ वर्षों में"काम के बदले अनाज कार्यक्रम" को **"राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम"** में बदल दिया जाएगा जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम पर आधारित होगा। इस विषय में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा विधेयक का एक मसौदा तैयार किया जा चुका है जिस पर इन दिनों विचार किया जा रहा है।

रोजगार प्रधान विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र, ग्रामोद्योगों और अनौपचारिक क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमारी सरकार अनुकूल नीतिगत वातावरण बनाने तथा इन क्षेत्रों के विकास के लिए सीधी सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है, जिसके लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल विकास, ऋण सहायता और विपणन सहायता पर जोर दिया जाएगा। हमने अनौपचारिक क्षेत्र में उद्यमों की कठिनाइयों पर विचार करने के लिए पहले ही एक आयोग का गठन कर दिया है जो शीघ्र ही उस सहायता के स्वरूप और गुंजाइश पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा जो इन उद्यमों को सरकार से अपेक्षित होगी।

आधारभूत संरचना क्षेत्र में भारी निवेश के जरिए अकुशल व अर्द्ध कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किये जा सकते हैं। चूंकि आधुनिक आधारभूत ढांचे का निर्माण करना हमारी सरकार की एक सर्वोच्च प्राथमिकता है, अतः हमें उम्मीद है कि इससे रोजगार के पर्याप्त अवसर उत्पन्न होंगे। मेरे सम्मानित मित्र एवं सहयोगी श्री लालू प्रसाद जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि हमारे राष्ट्रीय आधारभूत ढांचे के निर्माण में रेलवे सबसे आगे रहेगा।

हमारे मजदूरों का कौशल स्तर चिंता का विषय है। विनिर्मित उत्पाद की गुणवत्ता और श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी मुख्यतः श्रमिक बल की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। निवेश खासकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के लिए क्वालिटी वाले श्रम बल का होना बहुत जरूरी है। आय, उत्पादकता तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमें सभी क्षेत्रों में अपने मजदूरों के कौशल स्तर को ऊंचा करना होगा। इसके लिए बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं की आवश्यकता है। 397 मिलियन श्रमिक बल का लगभग 67% हिस्सा या तो निरक्षर है या नाममात्र का ही साक्षर है। महत्वपूर्ण बात

यह है कि 20-24 वर्ष की आयु वर्ग में कामगारों का केवल 5% ही व्यावसायिक रूप से कुशल है। यहाँ तक कि शिक्षित बेरोजगारों में भी थोड़े बहुत ही व्यावसायिक कौशल रखते हैं। इसका समाधान स्वतः स्पष्ट है। हमें कामगारों का कौशल बढ़ाने और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने में पर्याप्त निवेश करना होगा। इसके फलस्वरूप, हम एक उत्तरोत्तर बढ़ते कुशल कामगारों का विशाल भंडार तैयार कर पाएंगे। अंततोगत्वा, रोजगार सृजन के लिए किसी भी रणनीति में यह सुनिश्चित करना होगा कि उच्च उत्पादकता और उच्च गुणवत्ता वाले कार्य के लिए कार्यबल में शामिल होने वाले सभी नए कामगार अपेक्षित कौशल संपन्न हों।

अपने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें नए समाधान खोजने होंगे। अपने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.आई.टी.) और प्रशिक्षण योजनाओं को मजबूत और आधुनिक बनाने के साथ-साथ हमें यह भी समझना होगा कि इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने और इनका प्रबंध करने के लिए निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों में ही उद्योगों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाए। हमें अन्य देशों, विशेषकर जर्मनी जहां उद्योग जगत अप्रेंटिस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेता है और दक्षिण-पूर्व एशिया से , जहां उद्योग जगत सक्रिय रूप से प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन में सक्रिय रूप से शामिल हैं, से बहुत कुछ सीखना होगा।

हाल के वर्षों में राष्ट्रीय विकास के निर्धारकों में परिवर्तन आया है और निकट भविष्य में इनमें और बदलाव आने की आशा है। शिक्षा के स्तरों में तेजी से वृद्धि, तकनीकी नवीनताओं और उपयोगों की उच्च दर और तेज तथा सस्ती संचार व्यवस्था जैसे कारण सामाजिक परिवर्तन की रफ्तार में तेजी लाने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं। हम यह कह सकते हैं कि विकास का भावी रास्ता तय करने में प्रौद्योगिकी, संगठन, सूचना और शिक्षा तक पहुँच और उत्पादक कौशल के विकास की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होगी। हमारे देश में प्रशिक्षित वैज्ञानिक कर्मियों का एक शानदार आधार है। इसका श्रेय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू को जाता है। हमारे सामने यह चुनौती कि हमें अपने श्रमिकों के ज्ञान तथा कौशल को समृद्ध बनाने के लिए ज्यादा अवसरों के सृजन हेतु अपनी बड़ी श्रम शक्ति के साथ इन वैज्ञानिक क्षमताओं को समन्वित करना होगा। प्रशिक्षण और नए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से उनके कौशल को उन्नत बनाने का प्रयास अन्ततः यह सुनिश्चित करेगा कि हमारी श्रमशक्ति प्रौद्योगिकी क्रान्ति के अद्यतन विकास से सुपरिचित रहे। इस परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक शिक्षा की पहुँच को सार्वभौमिक बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। जब मैं अपने पड़ोस के देशों की ओर, उदाहरण के लिए, दक्षिण कोरिया की तरफ देखता हूँ तो पाता हूँ कि माध्यमिक स्कूल की आयु का हरेक बच्चा स्कूल में हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम अपने देश में सभी बच्चों को अभी तक प्रारंभिक शिक्षा तक नहीं दे पाए हैं। यदि हमें विकास की अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना है तो हमें इस अंतर को पाटना होगा।

तथापि, प्रशिक्षण के अलावा हमें रोजगार वृद्धि पर श्रम कानूनों सहित अपनी आर्थिक नीतियों के प्रभाव की समीक्षा भी करनी होगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अपनी आर्थिक नीतियों में अन्तर्निहित प्रोत्साहन पद्धति रोजगार वृद्धि को हतोत्साहित करने के बजाय अधिकाधिक प्रोत्साहित करे। हमारी वित्तीय और आर्थिक नीतियों द्वारा पूंजी पर आधारित और श्रम बचत करने वाले उद्योगों की बजाय श्रम पर आधारित उद्योगों एवं प्रक्रियाओं के विकास को प्रोत्सहित किया जाना चाहिए। श्रम बाजारों के कार्य और अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि पर इसके प्रभाव पर ईमानदारी से बहस होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि यह एक बहुचर्चित विषय है और यह अनेक विवादों को भी जन्म देता है।

श्रम बाजारों में अधिक लचीलेपन की आवश्यकता को पहचानते हुए हमें जरूरत पड़ने पर लोगों को नौकरी पर रखने और जरूरत न होने पर निकाल देने की नीति को आसानी से मंजूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगार बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था लागू नहीं है। फिर भी, जैसा कि हम मांग में काफी अनिश्चितता और उतार-चढ़ाव के साथ-साथ तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी परिस्थितियों वाली दुनिया में रह रहे हैं अतः रोजगार पर श्रम कानूनों साहित हमारी आर्थिक नीतियों के प्रभाव का ईमानदारी से सार्थक आकलन होना चाहिए। लोकतंत्र में स्थायी बुनियादी सुधार लाने के लिए सभी पणधारों विशेषकर कामगारों और मजदूर संघों से बातचीत करना जरूरी हैं। हमारी सरकार मानवीय चेहरे वाले सुधारों के प्रति वचनबद्ध है। हमारे देश के श्रमिकों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम कभी भी ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे जिससे मजदूरों और हमारे देश के मेहनतकश वर्गों के हितों पर बुरा असर पड़े।

मैं आशा करता हूँ कि इनमें से कुछ मुद्दों पर हमारे द्वारा गठित राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद और अनौपचारिक क्षेत्र पर गठित आयोग में चर्चा की जाएगी। मैं व्यापार एवं श्रम संगठनों से आग्रह करता हूँ कि वे राष्ट्रीय महत्व के इन मुद्दों पर सरकार के साथ सार्थक विचार-विमर्श करें ताकि हम एक आधुनिक प्रतिस्पर्धी राष्ट्र के रूप में उन्नति कर सकें।

इन शब्दों के साथ, मैं श्रम पुरस्कारों के विजेताओं और उनके संगठन के प्रबंधन को फिर एक बार बधाई देता हूँ जिन्होंने उनको उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने में अपेक्षित सहयोग दिया। राष्ट्र-निर्माण के कार्य को पूरा करने के लिए हमारे देश को उत्कृष्टता और सामाजिक समता हासिल करने की चाहत की दोहरी प्रतिबद्धता की जरूरत है। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि पुरस्कार विजेता हम सभी को ऊँचा लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करेंगे। हम यथा-स्थिति से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। पंडित जी कहा करते थे कि हमें उपलब्धि हासिल करने से पहले काफी रास्ता तय करना है। अतः हमें अपने लिए ऊँचा लक्ष्य निर्धारित करना है ताकि हम सामूहिक रूप से एक नए भारत के निर्माण के सपने को साकार कर सकें – ऐसा भारत जो अभाव और शोषण से मुक्त हो। यही मेरी कामना है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्रतिभा आज मैंने इस हॉल में देखी है वह इस बात का संकेत है कि भारत सामाजिक समता के प्रति प्रतिबद्ध, गरीबी उन्मूलन के लिए समर्पित, अज्ञानता और बीमारी, जिससे हमारे देश के लाखों लोग अभी भी प्रभावित है, के निवारण के लिए प्रौद्योगिकीय रूप से अग्रणी, परिष्कृत तथा मानव कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है।

******